



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 7, 2019/आश्विन 15, 1941

No. 321]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2019/ASVINA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2019

फा. सं. 9/1/2013-ईसीबी(पीटी-2).—केंद्रीय सरकार, निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

1. (1) इस स्कीम को निक्षेपागार प्राप्ति (संशोधन) स्कीम, 2019 कहा जा सकेगा।
(2) यह स्कीम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. (1) निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 में, पैराग्राफ 2, खंड 1, उप-खंड (छ) में शब्द "विदेश" का लोप कर दिया जाएगा।
(2) अनुसूची 1 में, क्रमांक 34 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"35. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2018 के अंतर्गत भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र"।

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 को दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 9/1/2013-ईसीबी के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2019

F. No. 9/1/2013-ECB(Pt-2).—The Central Government hereby makes the following amendments to the Depository Receipts Scheme, 2014, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Depository Receipts (Amendment) Scheme, 2019.
(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. (1) In the Depository Receipts Scheme, 2014, in paragraph 2, clause 1, sub-clause (g), the word “foreign” shall be omitted.
(2) In Schedule 1, after serial number 34, the following shall be inserted, namely:-
“35. International Financial Services Centre in India set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 OF 2005).”

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The Depository Receipts Scheme, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide notification number 9/1/2013-ECB, dated the 21st October 2014.